लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1862

29 नवंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

कपड़ा उत्पादन की मात्रा

1862. एडवोकेट ए. एम. आरिफः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में वस्त्र उद्योग के विकास और विस्तार के लिए एक प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत इस प्रयोजनार्थ क्षेत्र-वार कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ग) इस योजना के माध्यम से कपड़ा उत्पादन, रोजगार के अवसरों के सृजन और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केरल में निर्माणाधीन वस्त्र निर्यात केंद्र के विकास पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग): वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों/सेगमेंटों का संवर्धन और विकास करने के लिए सरकार विभिन्न नीतिगत पहलें और योजनाएं क्रियान्वित कर रही है जिनसे अन्य बातों के साथ-साथ रोजगार सृजन के माध्यम से वस्त्र कामगारों के जीवन और जीविकोपार्जन में सहायता और सुधार होता है तथा वस्त्र उद्योग के उत्पादन और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का संवर्धन करता है, जैसे कि :

- **हथकरघा क्षेत्र:** सरकार देशभर में हथकरघों के संवर्धन और बुनकरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं चला रही है:-

  (1): राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)
  (2: व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)
  (3): हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्लयूएस)
  (4): यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत कच्ची सामग्री, करघों और उपस्करों की खरीद, डिजाइन नवाचार, उत्पाद विविधीकरण, अवसंरचना विकास, कौशल उन्नयन, लाइटिंग यूनिट, हथकरघा उत्पादों के विपणन और रियायती दरों पर ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित और जारी की गई योजना-वार निधियां नीचे दी गई हैं:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
		आबंटित निधि (सं.प्रा.)	जारी निधि	आबंटित निधि (सं.प्रा.)	जारी निधि	आबंटित निधि (सं.प्रा.)	जारी निधि
1	**राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम**	167.53	153.56	140.24	135.05	138.53	119.72
2	**व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना**	50.00	40.11	32.50	31.82	21.50	16.38
3	**हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना**	26.56	26.56	25.00	24.98	10.05	2.06
4	**यार्न आपूर्ति योजना**	261.50	261.35	200.00	199.84	155.41	126.84
	कुल	**505.59**	**481.58**	**397.74**	**391.69**	**325.49**	**265.00**

इस क्षेत्र में बुनकरों द्वारा प्रयोग किए गए मुख्य फाइबर, कपास, रेशम, ऊन, लिनिन, पटसन और एक्रिलिक हैं। बुनकरों और उनके परिवारों की आंतरिक खपत के लिए इस क्षेत्र द्वारा बहुत से हथकरघा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र की असंगठित और परंपरागत प्रकृति के कारण हथकरघा उत्पादन से संबंधित आंकड़ा बिखरा हुआ है और केंद्रीय रूप से मात्रा आधारित करने के लिए उपलब्ध नहीं है। चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना (2019-20) के अनुसार देश में 35.22 लाख हथकरघा कामगार तैनात हैं और उपर्युक्त योजनाएं हथकरघा बुनकरों को उनके वर्तमान व्यवसाय में रोजगार को कायम रखने के लिए सहायता प्रदान कर रही हैं। जहां तक विदेशी मुद्रा की आय का संबंध है, पिछले तीन वर्षों के दौरान हथकरघा निर्यात से संबंधित लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई है:

क्र.सं.	वर्ष	लक्ष्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)	उपलबिध (मिलियन अमरीकी डॉलर में)
1	2016-17	450	357.58
2	2017-18	463	353.92
3	2018-19	400	343.43

- **पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस)**: वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों में अवसंरचना, क्षमता निर्माण तथा विपणन सहायता उपलब्ध कराकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग का संवर्धन करना। इस योजना में वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान कुल 500 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा

गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य तथा सिक्किम में प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर औद्योगिक परिधान मशीनरी से पूर्णतया सुसज्जित अपैरल एवं परिधान निर्माण केंद्रों (फैक्ट्रियों) की स्थापना की गई है। प्रत्येक केंद्र को 1200 लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने हेतु डिजाइन किया गया है। रेशम उत्पादन के अंतर्गत सभी पूर्वोत्तर राज्यों में मलबरी, एरी तथा मूगा क्षेत्रों को शामिल करते हुए कुल 38 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है जिनकी कुल लागत भारत सरकार की 955.07 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी सहित 1106.97 करोड़ रुपए है।

- **सिल्क समग्र**: भारत सरकार वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिए 2161.68 करोड़ रुपए के परिव्यय से देश में रेशम उत्पादन के विकास के लिए 'सिल्क समग्र' नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का क्रियान्वयन कर रही है जो मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का अंतरण तथा आई.टी. पहलों, बीज संगठनों को सहायता, समन्वय एवं बाजार विकास तथा गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली (क्यूसीएस)/निर्यात ब्रांड संवर्धन तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन पर केंद्रित है। ऊन, कयर, कपास जैसे अन्य फाइबरों को साथ मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग वाले नए उत्पादों का विकास करने के लिए आरएंडडी प्रयास भी शुरू किए गए हैं।

वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए कच्ची रेशम का उत्पादन लक्ष्य एवं प्राप्ति तथा अनुमानति रोजगार सृजन का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

वर्ष	**कच्ची रेशम का उत्पादन (एमटी)**		**रोजगार सृजन (मिलियन व्यक्ति)**
	लक्ष्य	**उपलब्धि**	
2017-18	33840	31906	8.60
2018-19	35960	35468	9.18
2019-20	38530	15645(सितंबर, 19)	10.00 (लक्ष्य)

- **पावर टेक्स इंडिया:** व्यापक विद्युतकरघा क्षेत्र योजना तीन वर्ष के लिए 487 करोड़ रुपए के परिव्यय से अप्रैल, 2017 में शुरू की गई थी। इस योजना में विद्युतकरघा उन्नयन; अवसंरचना निर्माण, रियायती ऋण की उपलब्धता से संबंधित संघटक हैं। इस योजना को विद्युतकरघा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने और 10,000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए बनाया गया है और इससे विद्युतकरघा इकाइयों को अधिक लाभ भी होगा। पावर टेक्स इंडिया योजना के अंतर्गत उक्त योजना के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट की गई कुल निधियां 487.07 करोड़ रुपए है।

- **वस्त्र और अपैरल क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज**: अपैरल और मेड-अप क्षेत्र में रोजगार और निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए जून, 2016 में 6000 करोड़ रुपए का पैकेज शुरू किया गया था। इस पैकेज में परिधान और मेड-अप्स के लिए राज्य लेवियों में छूट, परिधान के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत

अतिरिक्त उत्पादन और 10% रोजगार संबद्ध सब्सिडी, ईपीएफ के लिए नियोक्ता के समग्र 12% अंशदान के लिए सहायता, परिधान में निर्धारित अवधि का रोजगार, ओवरटाइम की सीमा को बढ़ाना तथा परिधान क्षेत्र के लिए धारा 80जेजेएए के अंतर्गत आयकर में छूट शामिल है।

- **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस):** संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) की शुरूआत जनवरी, 2016 में 17,822 करोड़ रुपए के परिव्यय से की गई थी। इस योजना को वर्ष 2022 तक लगभग 95,000 करोड़ रुपए का नया निवेश आकर्षित करने तथा 35 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश में आसानी से व्यवसाय करने का संवर्धन करना और रोजगार सृजन के लक्ष्य को प्राप्त करना तथा विनिर्माण में 'जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट' के साथ मेक इन इंडिया के माध्यम से निर्यात का संवर्धन करना है।

वस्त्र क्षेत्र भारत सरकार की मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण युवा रोजगार की प्रमुख पहलों के अनुरूप है और वर्तमान वस्त्र क्षेत्र देशभर के 4.5 करोड़ कामगारों को रोजगार प्रदान करता है और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ):जी, नहीं। अभी तक केरल में वस्त्र निर्यात केंद्र के विकास के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

****